

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2
उत्तर देने की तारीख-22/07/2024

सरकारी विद्यालयों/नए स्वीकृत केंद्रीय विद्यालयों में
केंद्रीय निधि का उपयोग

†2. डॉ. के. सुधाकर:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास कर्नाटक के सरकारी विद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा उपयोग की गई केन्द्रीय निधि के संबंध में आंकड़े उपलब्ध हैं, यदि हां, तो चिकबल्लापुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि कर्नाटक के कई सरकारी विद्यालयों में अभी भी मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं का अभाव है, यदि हां, तो कर्नाटक राज्य को और उसके द्वारा प्रदत्त उपयोग की गई केन्द्रीय निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कर्नाटक में नए केन्द्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का चिकबल्लापुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में एक नया केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चिकबल्लापुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में कार्यान्वित कार्यक्रमों और इस संबंध में संस्वीकृत, उपयोग और व्यपगत निधि के संबंध में आंकड़े क्या हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयंत चौधरी)

(क): केंद्र सरकार वर्ष 2018-19 से समग्र शिक्षा नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रही है। यह स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए प्री-स्कूल से बारहवीं कक्षा तक विस्तारित एक व्यापक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। कर्नाटक राज्य के लिए केन्द्र और राज्य के बीच निधियों में हिस्सेदारी की पद्धति 60:40 के अनुपात में है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान

चिक्काबल्लापुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित कर्णाटक के सरकारी स्कूलों में राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य	वित्त वर्ष	कुल व्यय (लाख रुपए में)
कर्नाटक	2021-2022	1,24,390.17
	2022-2023	1,13,039.69
	2023-2024	1,46,811.38

स्रोत: प्रबंध पोर्टल

(ख): समग्र शिक्षा योजना स्कूल में बुनियादी सुविधाओं के निर्माण में सहायता करती है। इस संबंध में, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं और प्रत्येक वर्ष के आरंभ में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) तैयार किया जाता है। इसके बाद इन योजनाओं का मूल्यांकन/अनुमोदन परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानकों तथा बजटीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है। यूडीआईएसई+ 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक के संबंध में बुनियादी सुविधाओं वाले सरकारी स्कूलों का प्रतिशत इस प्रकार है:

क्र.सं.	सुविधा	प्रतिशतता
1.	विद्युत	99.1
2.	लड़कों के शौचालय	94.9
3.	लड़कियों के शौचालय	98.1
4.	पेयजल	99.6
5.	लाइब्रेरी या रीडिंग कॉर्नर या बुक बैंक	97.5

स्रोत: यूडीआईएसई+ 2021-22

समग्र शिक्षा के तहत बुनियादी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के संबंध में, कर्नाटक राज्य के लिए वर्ष 2018-19 से वर्ष 2024-25 (जून 2024 तक) तक स्वीकृत निधि और किया गया व्यय नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	घटक	वित्तीय स्वीकृति (लाख रुपये में)	व्यय (लाख रुपए में)
1.	पुस्तकालय कक्ष	75.60	52.06

क्र.सं.	घटक	वित्तीय स्वीकृति (लाख रुपये में)	व्यय (लाख रुपए में)
2.	लड़कियों के शौचालय	159.50	129.35
3.	लड़कों के शौचालय	162.00	122.85
4.	पेयजल	3.50	3.25
5.	प्रमुख मरम्मत	6322.96	748.61
	कुल	6723.56	1056.12

(राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार)

(ग) और (घ): नए केन्द्रीय विद्यालयों (केवी) को खोलना एक सतत प्रक्रिया है और जब कोई प्रस्ताव केवीएस के निर्धारित मानदंडों और मापदंडों को पूरा करता है, तो उस पर विचार/अनुमोदन के लिए कार्रवाई की जाती है। अब तक की स्थिति के अनुसार, गौरीबिदानूर में चिकबल्लापुर लोकसभा क्षेत्र में वर्ष 2018 से एक केन्द्रीय विद्यालय पहले से ही कार्य कर रहा है।

(ङ) समग्र शिक्षा के तहत, चिक्काबल्लापुर लोकसभा क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 तक) के दौरान जारी निधि, किए गए व्यय और शेष धनराशि का ब्यौरा इस प्रकार है:

रु. लाख में

क्र.सं.	वर्ष	जारी की गई निधियां	व्यय	शेष धनराशि
1	2019-20	17453.21	17398.91	54.30
2	2020-21	3825.59	3745.19	80.40
3	2021-22	4147.84	3910.36	237.48
4	2022-23	4775.28	4678.65	96.63
5	2023-24	6301.14	6037.45	263.69
	कुल	36503.06	35770.56	732.5

टिप्पणी शेष अनुदान का उपयोग अगले वित्त वर्ष के दौरान किया जाता है

(राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार)
